



राजस्थान भाजपा के विधायकों और सांसदों के लिए गुजरात के केवडिया में आयोजित हो रहे प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों के साथ पीछे की पंक्ति में बैठकर प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के तीनों सत्रों में वे आम विधायक की तरह मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने अंतिम पंक्ति में बैठ कर प्रशिक्षण लिया

आज के तीनों सत्रों में मुख्यमंत्री से मंच पर बैठने का आग्रह किया गया, पर वे आम विधायक के रूप शिविर में उपस्थित रहे

जयपुर, 6 मई। भाजपा के विधायकों और सांसदों के लिए गुजरात के केवडिया में आयोजित हो रहे तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज तीन सत्र आयोजित हुए। केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिव प्रकाश और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने विधायकों और सांसदों को सुशासन का पाठ पढ़ाया। तीनों सत्रों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों के साथ पीछे की पंक्तियों में बैठकर प्रशिक्षण लिया। मुख्यमंत्री शर्मा को मंच पर और आगे की पंक्तियों में बैठने का आग्रह किया गया। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। वे तीनों सत्रों में आम विधायक की तरह मौजूद रहे। वहीं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा,

■ **प्रशिक्षण शिविर में केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री, शिवप्रकाश व राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने विधायकों को विभिन्न विषय समझाए।**

केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और विधायक अनिता भटेल मुख्य वक्ता के साथ मंच पर मौजूद रहे। शिविर के दूसरे दिन पहले सत्र में केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने राजस्थान के संदर्भ में “मोदी सरकार की परिवर्तनकारी नीतियाँ” विषय पर चर्चा की। उन्होंने इस विषय पर जोर दिया कि विकसित भारत-विकसित राजस्थान की संकल्पना को पूरा करने वाली केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को किस तरह से सफल किया जाए।

दूसरे सत्र में राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिव प्रकाश की चर्चा का विषय था कि भाजपा और अन्य दलों के बीच वैचारिक मतभेदों और अन्य दलों की विघटनकारी नीतियों से किस तरह सावधान रहा जाए। उन्होंने भाजपा विधायकों और सांसदों को भाजपा के मूलभूत सिद्धांतों, राष्ट्रीयता और समग्र विकास के दृष्टिकोण के बारे में बताया। तीसरे सत्र में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में “सोशल मीडिया एवं विमर्श निर्माण-हमारी

भूमिका” विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह राष्ट्रीय भावना का निर्माण किया जाए, इसकी जानकारी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी विधायकों और सांसदों को ठेकेदारों से सावधान रहने की नसीहत दी थी।

उन्होंने सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि जिन लोगों से आप 24 घंटे घिरे रहते हो, वो ज्यादा काम आने वाले नहीं हैं। पार्टी के मूल वोटर पर पकड़ जरूरी है, ऐसे लोगों से घिरे होने की वजह से मूल वोटर नाराज होकर छिटक जाता है।

पाकिस्तान बॉर्डर पर, वायुसेना आज करेगी युद्धाभ्यास

नई दिल्ली, 06 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण रिश्तों के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। भारत 7 और 8 मई को पाकिस्तान बॉर्डर के पास बड़ा हवाई अभ्यास करने जा रहा है। इस संबंध में भारत ने नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इस अभ्यास में, भारतीय वायु सेना राजस्थान में बॉर्डर के पास अपनी ताकत दिखाएगी। सीमा पर तनाव को देखते हुए, यह अभ्यास भारत की सतर्कता का संकेत है।

भारतीय वायु सेना 7 और 8 मई को राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास एक बड़ा हवाई अभ्यास करेगी। इसके लिए एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। नोटिस टू एयरमैन का मतलब

■ **राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर दोपहर 3.30 बजे युद्धाभ्यास शुरू होगा और 8 मई रात 9.30 तक चलेगा।**

है, विमान पायलट को दी जाने वाली सूचना। सूत्रों के मुताबिक, यह एक्सरसाइज एयरफोर्स कई जगहों पर एक साथ करेगा। एयरफोर्स के अलग-अलग बेस से फाइटर उड़ान भरेंगे। जैसलमेर, पोखरण, जोधपुर और बीकानेर में यह एक्सरसाइज होगी। इसमें फाइटर जेट रफाल, सुखोई-30, मिराज भी शामिल होंगे। नोटिस टू एयरमैन के अनुसार, ये अभ्यास 7 मई को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और 8 मई को रात 9:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान, उस क्षेत्र में विमानों की आवाजाही पर कुछ रोक रहेगी। इस अभ्यास में, फाइटर जेट के साथ-साथ सर्विलांस एयरक्राफ्ट शामिल होंगे।

राहुल गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी भारत की तरफ आंख उठा कर न देख सके।” उन्होंने आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की और कहा कि आज पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश न्याय का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बी. के. हरप्रसाद, सह प्रभारी, प्रफुल्ल विनोद शाह, राज्य अध्यक्ष उदयभानु, रोहतक के सांसद दीपेन्द्र हुड्डा और पूर्व विधायक सुमित सिंह भी मौजूद थे।

भारत में 2 5 9 जिलों में आज होगी मॉक ड्रिल

गृह मंत्रालय ने उन जिलों की लिस्ट जारी की जहां मॉक ड्रिल होगी

नई दिल्ली, 06 मई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच बुधवार को देश के 259 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी-1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी-3 कम संसिटिव हैं। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई हाईलेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद थे। दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश के कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। जरूरी नहीं ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट सामान्य एडमिनिस्ट्रिटिव डिस्ट्रिक्ट हों। जैसे-

- **मॉक ड्रिल के लिए जिलों को संवेदनशीलता के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है**
- **पहले वर्ग में अति संवेदनशील जिलों को रखा गया है। इसमें 13 जिले हैं दूसरे संवेदनशील वर्ग में 201 जिलों को तथा तीसरे कम संवेदनशील वर्ग में 45 जिलों को रखा गया है।**

उत्तर प्रदेश में कुल 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को इनके इंपोर्टेंस या सेसेटिविटी के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे संसेटिव हैं। ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे- उत्तर प्रदेश में केवल 1 डिस्ट्रिक्ट - बुलंदशहर कैटेगरी 1 में है क्योंकि यहां नौरा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 201 जबकि कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नागरिकों को यह हिदायत भी दी जाएगी कि वे मेडिकल किट, राशन, टॉच और

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वैंबसाइट पर संपत्ति घोषित की

नयी दिल्ली, 06 मई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजिव खन्ना समेत अधिकतर न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर 33 न्यायाधीशों में से 21 ने सोमवार को अपनी संपत्ति घोषित की। न्यायाधीशों अपने खुद के अलावा जीवनसाथी की संपत्ति भी सार्वजनिक कर दी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के लिये राहुल गांधी को, तथा उस माँग को स्वीकार करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।

‘ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सदा राष्ट्रहित सर्वप्रथम होता है ’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रशिक्षण शिविर में कहा, कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देखकर काम करती है

■ **मुख्यमंत्री ने शिविर में अपने संबोधन में कहा कि जयपुर में मेट्रो विस्तार के लिए डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है। केन्द्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी भी बना ली गई है।**

जनप्रतिनिधियों को नीति और रणनीति सिखाने के साथ ही, नैतिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी सशक्त करेगा।

प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जो 37 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर किए हैं, उनसे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा।

शर्मा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 96 हजार से अधिक शहरी और ग्रामीण आवास बनाए जा चुके हैं तथा 5 लाख 48 हजार से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं।

प्रशिक्षण शिविर में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ ही बुनियादी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है तथा केन्द्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी बना ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (माा) प्रारंभ की है।

इस अवसर पर राजस्थान के भाजपा सांसदगण, विधायकगण, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

एयरपोर्ट को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कहा गया कि दिनांक 15 व 16 फरवरी को उनके ईमेल एड्रेस पर मेल प्राप्त हुआ। जिसमें कहा गया कि जयपुर एयरपोर्ट पर अलग-अलग समय पर बम विस्फोट किया जाएगा। जिसकी आरंभिक सूचना 16 फरवरी को दी जा चुकी थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्त ने कहा कि उसने अज्ञानतावश मेल कर दिया था।

मेन लाइन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर पहुंच गये हैं तथा यह बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। सोशल मीडिया को बैन करना असम्भव है तथा जो प्लेटफॉर्म अस्तित्व में हैं, वे डिलीट नहीं किये जा सकते।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान से की कड़ी पूछताछ

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की “झूठी” कहानी को खारिज किया

संयुक्त राष्ट्र/नई दिल्ली, 06 मई। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान सदस्यों ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे बयान को मानने से इनकार कर दिया और पूछा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा परिषद में सोमवार को इस्लामाबाद द्वारा प्रस्तावित अनौपचारिक बैठक में सदस्यों ने बंद करने में पाकिस्तान से कठिन सवाल किया। सदस्यों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षणों और परमाणु बयानबाजी की आलोचना की। सूत्रों ने कहा कि सदस्यों ने पाकिस्तान से भारत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा है। सूत्रों ने कहा, कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु बयानबाजी तनाव बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। स्थिति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान

■ **सुरक्षा परिषद सदस्यों ने मिसाइल टैस्ट के लिए और परमाणु युद्ध की बयानबाजी के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की।**

के प्रयास भी विफल रहे। उसे भारत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी गई। सूत्रों ने इस्लामी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकवादी हमले का हवाला देते हुए बताया, आतंकवादी हमले की व्यापक निंदा की गई और जवाबदेही पर बल दिया गया। कुछ सदस्यों ने विशेष रूप से धार्मिक आस्था के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यों ने अनौपचारिक सत्र में पाकिस्तान से कठिन सवाल पूछे। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे बयान को मानने से इनकार कर दिया और पूछा कि क्या

लश्कर-ए-तैयबा के हमले में शामिल होने की संभावना है। मई महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्रीस ने पाकिस्तान के अनुरोध पर सोमवार को बैठक निर्धारित की थी। पाकिस्तान अभी परिषद में अस्थायी सदस्य है। बैठक के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह में दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है और उसके सूचना मंत्री और रक्षा मंत्री ने आक्रामक बयान जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि भारत द्वारा बहुत जल्द पाकिस्तान पर हमला करने की संभावना है।

पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गयी है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी सीमा चौकी को बंद करने, पाकिस्तान के साथ सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापारिक संपर्कों को बंद करने के साथ-साथ, डाक संपर्कों को भी बंद करने का फैसला किया है।

सड़क हादसे में घायलों को पूरे देश में मुफ्त इलाज मिलेगा

नई दिल्ली, 06 मई। भारत सरकार ने पूरे देश में कैशलेस ट्रैटमेंट स्कीम (नकद रहित इलाज योजना) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार हर व्यक्ति को प्रति हादसा अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी भी व्यक्ति का मोटर वाहन के कारण सड़क पर एक्सिडेंट होता है, तो उसे इस स्कीम के तहत देश के किसी भी हिस्से में इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। हादसे के शिकार व्यक्ति को सरकार या नामित अस्पतालों में इलाज के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। इस योजना के तहत पीड़ित व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अगले सात दिनों तक, अधिकतम

1,50,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यह सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में पूरी तरह लागू होगी जो सरकार द्वारा "नामित" किए गए हैं। अगर किसी कारणवश पीड़ित को नामित अस्पताल नहीं मिल पाता और इलाज किसी अन्य अस्पताल में कराया जाता है। तो उस स्थिति में उस अस्पताल में सिर्फ स्थिर हालत (स्टेबलाइजेशन) तक का इलाज ही इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस बारे में अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सौंपी गई है। यह संस्था पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल इस योजना की नोडल एजेंसी होगी। यह काउंसिल इस बात की निगरानी करेगी कि योजना को ठीक से लागू किया जाए।

जयराम रमेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जरूरत नहीं समझी। जयराम इस पद के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हैं। वे नहीं जानते कि मीडिया को कांग्रेस के पक्ष में कैसे किया जाये, और यह चीज कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। शुरुआत में ही, जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें हटाना चाहते थे, तो राहुल गांधी ही उनके समर्थन में आ गये थे। और अब, जब राहुल गांधी भी समझ गये हैं कि वे पार्टी के लिए बोझ हैं। वे न मीडिया को समझते हैं और न बोलने में ही माहिर हैं। लेकिन सोनिया गांधी उन्हें इस पद पर बनाए हुए हैं। जयराम रमेश ने खतरे को भांपते हुए खड़गे को थोड़ी चापलूसी करनी शुरू कर दी। उन्होंने खड़गे से कहा कि वे राजनीति में इतने वरिष्ठ हैं तथा उन्हें राजनीति का इतना लम्बा अनुभव है कि उन पर एक

किताब लिखी जानी चाहिए, जिसमें उनके जीवन, उनकी राजनैतिक यात्रा और पूरे दौर का विस्तृत वर्णन हो। यही नहीं, उन्होंने खड़गे पर इस प्रकार की किताब लिखने के लिए स्वयं को पेश भी कर दिया। खड़गे एक भले व्यक्ति है लेकिन उन्होंने दुनिया देखी है। वे तुरन्त जयराम की मंतव्य समझ गये, और जवाब में सिर्फ मुस्करा दिये। दरअसल, इस समय कांग्रेस को एक अच्छे मीडिया प्रभारी की जरूरत है, जिसके पास इस बात की तह तक पहुंचने की क्षमता हो कि पार्टी में निर्णय लेने वाले शीर्ष स्तर पर क्या चल रहा है। इसके साथ ही, वह किसी बात इस तरह घुमाकर प्रस्तुत करने की क्षमता एवं महारथ रखता हो कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी घुमा सके। जयराम का एक नकारात्मक पक्ष और भी है। वे अमित शाह के घोर प्रशंसक हैं तथा कई मुद्दों पर उनकी प्रशंसा करते हुए, लोगों ने छिपकर उन्हें सुना भी है।